सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 33 राँची, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

21 जनवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-23/2023 का० 353--खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक-1097 दिनांक-28. 03.2023 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से० (को०क्र0-78/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध मुख्यत: निम्नवत् 5(पाँच) आरोप प्रतिवेदित किया गया है:-

आरोप संख्या-1:- झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 के प्रावधानों (विशेषत: कंडिका-20(xix) एवं 20(xx)) का अनुपालन नहीं करने,

आरोप संख्या-2:- मनमाने तरीके से डीलरों को निलंबित करने एवं 10 दिनों के अंदर कार्यालय के कर्मियों के माध्यम से अवैध वसूली कर निलंबन मुक्त करने तथा गोदाम प्रबंधकों एवं डोर स्टेप डिलिवरी परिवहन अभिकर्त्ता से अवैध वसूली करने,

आरोप संख्या-3:- धान क्रय करने के उपरांत राशि के भुगतान करने में पारदर्शिता एवं समान भावना नहीं रखने, 52 पैक्स की खरीदारी के विरूद्ध मात्र 14 पैक्स के किसानों का भुगताने करने, गलत मंशा, अवैध राशि की उगाही एवं निजी स्वार्थ में किसानों के भुगतान में मनमानी एवं स्वेच्छाचारिता बरतने,

आरोप संख्या-4:- राशन काडधारियों के जाति में अवैध तरीके से परिवर्तन करते हुए गलत व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने,

आरोप संख्या-5:- राईस मिलों की टैगिंग सही तरीके से नहीं करने, ससमय CMR जमा करवाने हेत प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, हजारीबाग राईस मिल के पास खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में CMR लंबित रह जाने से 24,33,13,351/- रूपये की राजस्व क्षति होने आदि,

2. समीक्षोपरांत, श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 27026 (HRMS), दिनांक 23.08.2024 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 78/20), तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-362, दिनांक 07.03.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है ।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है ।

6. अतः श्री अरविन्द कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के आलोक में उक्त नियमावली के नियम-17 के तहत् पुनः जाँच करने तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण करने हेतु पुनः आगे जाँच किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्री अरविन्द कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के

समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ ।

8. श्री अरविन्द कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

9. विभागीय संकल्प संख्या 27026(HRMS), दिनांक- 23.08.2024 के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उप सचिव/ अवर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है ।

10. विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

11. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से० एवं श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 33 - 50